www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 168 नागपुर, सोमवार, 15 मई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

चेन्नई के स्टूडेंट ने बनाया दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट, नासा करेगी लांच

चेन्नई

भारत ने कुछ महीने पहले ही स्पेस में 104 सैटेलाइट एक साथ भेजकर एक नया कीर्तिमान बनाया था। अब भारत के हिस्से गर्व का एक और पल आने वाला है। जानकारी के मुताबिक, चेन्नई के 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट तैयार किया है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 साल के रिफत शाहरुख ने एक ऐसी चीज तैयार की है जिसे वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट बताया है। रिफत ने ये सैटेलाइट यूएस स्पेस एजेंसी नासा और आईडूडललर्निंग इंक (ग्लोबल एजुकेशन कंपनी) के सामूहिक तत्वाधान में आयोजित 'क्यूब्स इन स्पेस' कॉन्टेस्ट के दौरान बनाया। रिफत ने इस सैटेलाइट का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। इस सैटेलाइट का वजन 0.1 किलोग्राम है और ये स्मार्टफोन से भी हल्का है। खबर है कि नासा इस सैटेलाइट को 21 जून को स्पेस में लॉन्च भी करेगी। रिफत ने बताया कि ये सैटेलाइट रिइनफोर्स्ड कार्बन फाइबर पोलीमर का बना हुआ है, जो 12 मिनट की फ्लाइट में टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की तरह काम करेगा और भविष्य में किफायती अंतरिक्ष मिशन की योजना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों पर 11 हजार करोड़ खर्च करेगा केंद्र

नई दिल्ली

केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के सुकमा समेत देश के 44 नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की परियोजना पर जल्द काम शुरू करेगी। सुकमा में पिछले दिनों बड़ा नक्सली हमला हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना की कुल लागत का पांच प्रतिशत यानी 550 करोड़ रुपये रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती समेत प्रशासनिक खर्च के लिए अलग से रखे जाएंगे। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क संपर्क को सुधारने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल केंद्रीय प्रायोजित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को मंजूरी दी थी। परियोजना को जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लागू किया जाएगा। ये जिले सुरक्षा और संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। परियोजना के तहत 5411 किलोमीटर सड़कों और 126 पुलों का निर्माण किया जाएगा या उन्हें सुधारा जाएगा। इन जिलों में 11,724.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से काम कराया जाएगा। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ सप्ताह में परियोजना शुरू हो सकती है और इसकी शुरूआत के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त कर लिए गए हैं। इन 44 जिलों में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में हैं, जहां पिछले महीने नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान मारे गये थे। इस योजना में शामिल अन्य राज्यों में ओड़िशा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र हैं।

कहां गया मजदूरों के कल्याण का बीस हजार करोड़ - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली

निर्माण मजदूरों के कल्याण पर खर्च होने वाली विशाल धनराशि बीस हजार करोड़ रुपये का ब्यौरा नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कहां गया यह पैसा? कहीं यह धनराशि चाय पार्टी या अफसरों के सैर-सपाटे पर तो नहीं खर्च हो गई? उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से इस फंड का पता लगाकर न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया।

एनजीओ नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने उपरोक्त आदेश दिया। अपनी याचिका में एनजीओ ने आरोप लगाया है कि निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए रियल एस्टेट फर्मों से वसूले गए वैधानिक उपकर का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। याचिका में आगे कहा गया है कि इस फंड का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि लाभार्थियों की पहचान और उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कोई उपयुक्त तंत्र मौजूद नहीं है। इस पर कैग की ओर से दाखिल हलफनामे और रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्त की पीठ ने कहा, 'कैग को भी पता नहीं कि पैसा कहां है। यह 20,000 करोड़ रुपये के करीब है। पीठ ने सवालिया अंदाज में कैग से पूछा, 'यह पैसा कहां जा रहा है। क्या यह चाय पार्टी अथवा अधिकारियों के सैर-सपाटे पर खर्च हो गया? आपको (कैग) यह पता लगाना ही होगा।'

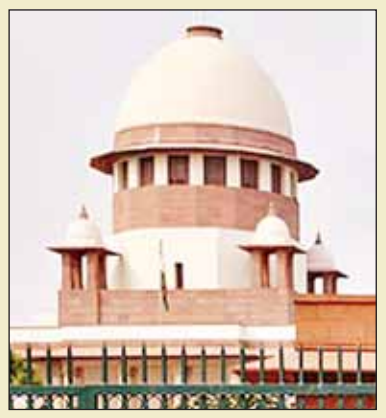

राज्यों ने कितनी राशि वसूली

अदालत ने जांच के लिए रास्ता भी सुझाया। अदालत ने कहा कि पहले तो यह पता लगाया जाए कि 1996 से लागू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट के तहत इस वर्ष 31 मार्च तक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने उपकर के रूप में कितनी राशि वसूल की। साथ ही यह भी पता लगाया जाए कि इस दौरान जुटाई गई धनराशि में से कितना पैसा कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड को दिया गया।

कैग यह सारा हिसाब-किताब जुटाए। अगर कहीं धनराशि का आवंटन अब तक नहीं किया गया है तो संबंधित बोर्ड को उक्त धनराशि छह हफ्ते में निर्गत कर दी जाए।

2015 में भी लगाई थी फटकार

ध्यान रहे कि इससे पूर्व 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण मजदूर कल्याण फंड का तकरीबन 26,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई थी।

उसने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार से इस फंड का पूरा ब्योरा देने के लिए कहा था।

हरियाणा ने वसूले 1314.86 करोड़ लेकिन बोर्ड को किए 52 करोड़

हरियाणा पर आरोप था कि उसने 1996 से 31 मार्च 2015 की अवधि में मजदूर कल्याण उपकर के रूप में 1314.86 करोड़ वसूले, लेकिन वेलफेयर बोर्ड को महज 52 करोड़ रुपये ही दिए।

इस पर उस समय कोर्ट ने कहा था कि मजदूरों का पैसा अधिकारियों और विज्ञापन पर खर्च कर दिया गया।

जांच एजेंसियों ने नहीं की दाऊद, हाफीज सईद के प्रत्यर्पण की मांग

नई दिल्ली

मुंबई आतंकी हमले (26/11) के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में वांछित दाऊद इब्राहिम के भारत प्रत्यर्पण को लेकर कोई आधिकारिक मांग नहीं की गई है। जांच एजेंसियों ने दोनों को भारत लाने के बारे में गृह मंत्रालय से अब तक कोई आग्रह नहीं किया है।

सूचना अधिकार (आरटीआइ) के तहत विदेश मंत्रालय के प्रत्यर्पण प्रकोष्ठ के सीपी-वी खंड से यह जानकारी प्राप्त हुई है। आरटीआइ के तहत विदेश मंत्रालय से जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद और भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को भारत लाने के बारे में की गई कार्रवाई के बारे में पूछा गया था। जवाब में कहा गया, भारत

में उक्त मामलों की जांच कर रही एजेंसियों की ओर से विदेश मंत्रालय को हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण/निर्वासन/वापसी को लेकर कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

काबिलेगौर है कि भारत लंबे समय से सार्क देशों के बीच एक प्रत्यर्पण संधि की वकालत कर रहा है। ऐसा इसलिए ताकि आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। मालूम हो, दाऊद पर 1993 बम धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है।

जाधव पर 18 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आमने-सामने भारत-पाक

नई दिल्ली

पाकिस्तान करीब अठारह साल पहले भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आइसीजे) में गया था। उस वक्त पाकिस्तान ने अपने नौसेना के विमान मार गिराए जाने को लेकर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इंसाफ की गुहार लगाई थी।

आज सोमवार से आइसीजे जो कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है वह कुलभूषण जाधव मामले की नीदरलैंड के हेग स्थित ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में सार्वजनिक रूप से सुनवाई करने जा रहा है। यहां पर दोनों पक्षों से जाधव मामले पर उत्पन्न विवाद को लेकर अपने-अपने तथ्य पेश करेंगे।

46 वर्षीय पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव मामले पर भारत ने

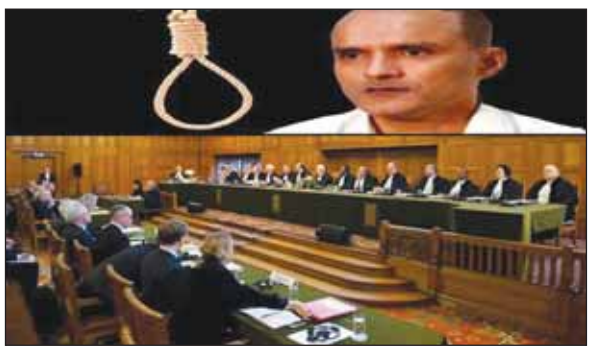

8 मई को संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक ईकाइ में याचिका दायर कर हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में भारत ने पाकिस्तान की तरफ से 16 बार कांसुलर एक्सेस को खारिज करने विएना संधि का उल्लंघन करार दिया है। पिछले महीने पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों के आरोप में कुलभूषण को फांसी की सज़ा सुनाई है। जाधव परिवार की तरफ से वीज़ा के लिए दिए आवेदन का भी पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। जाधव को पिछले साल 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

1999 में भारतीय वायुसेना ने मार गिराए पाक टोही विमान

इससे पहले 10 अगस्त 1999 को जब भारतीय वायुसेना ने कच्छ में एक पाकिस्तानी समुद्री टोही विमान अटलांटिक को सीमा में घुसकर निरीक्षण करते समय मार गिराया था। इस विमान शूटिंग में पाकिस्तान के 16 नौसैनिक मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान ने दावा करते हुए कहा कि उनके विमान को उनकी ही सीमा के अंदर मार गिराया गया और भारत से इसके लिए हर्जाने के तौर पर 60 मिलीयन डॉलर की भरपाई करने को कहा।

आईसीजे से पाक को मिला था झटका

अंतर्राष्ट्रीय अदालत की सोलह सदस्यीय न्यायिक पीठ ने साल 2000 की 21 मई को 14-2 मतों से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया। यह फैसला न्यायिक पीठ की अध्यक्षता कर रहे फ्रांस के गिलबर्ट गुईल्हेम ने भरी सभा में सुनाया।

जम्मू-कश्मीर: हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी ढेर

श्रीनगर

उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे हंदवाड़ा में रविवार को सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया, जबकि दक्षिण कश्मीर के त्राल में रहस्यमय धमाके में तीन लोग जख्मी हो गए। वहीं पिछले सप्ताह श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मीरबाजार हमले में मरने वालों की संख्या छह हो गई। अस्पताल में उपचाराधीन घायल ने दम तोड़ दिया।

हंदवाड़ा में मारे गए दोनों आतंकी विदेशी थे। वह पिछले सप्ताह राजवार के जंगल में सेना के तलाशी अभियान के दौरान बच निकले थे। दोनों को हंदवाड़ा में एक सैन्य शिविर पर आत्मघाती हमले का जिम्मा सौंपा गया था। इसका पता चलते ही सुरक्षाबल लगातार दबिश दे रहे थे। दोपहर को सेना और पुलिस के एक संयुक्त कार्यदल ने वारीपोरा-मागम में इनके छिपे होने का पता चलते ही तलाशी अभियान छेड़ा। आतंकियों ने जवानों को देख घेराबंदी तोड़ने के लिए फायरिंग कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायर किया। लगभग एक घंटे तक चली मुठभेड़ में दोनों आतंकी मारे गए। फिलहाल सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल के आसपास कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते तलाशी अभियान जारी रखा है। इससे पूर्व सुबह दक्षिण कश्मीर के सईदाबाद त्राल (पुलवामा) में बिजली के ट्रांसफार्मर के पास अचानक हुए धमाके में तीन ग्रामीण जख्मी हो गए।

चीन के सम्मेलन में नहीं शामिल हुआ भारत

पाक-यूएस सहित 29 देश हुए शरीक

बीजिंग

भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को लेकर संप्रभुता संबंधी चिंता के चलते आज चीन के बेल्ट एंड रोड फोरम के उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लिया। समारोह को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने संबोधित किया जिसमें कोई भारतीय प्रतिनिधिमंडल नजर नहीं आया। पूछे जाने पर भारतीय राजनयिकों ने बीती रात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले द्वारा जारी बयान की ओर संकेत किया। बागले ने कहा था कोई भी देश ऐसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता, जिसमें उसकी संप्रभुता एवं भूभागीय एकता संबंधी प्रमुख चिंताओं की उपेक्षा की गई हो। बैठक में कुछ भारतीय शोधार्थियों ने हिस्सा लिया।

29 देशों ने लिया हिस्सा

उन्होंने बताया कि कोई भारतीय प्रतिनिधिमंडल नजर नहीं आया। जिस सभागार में समारोह हुआ उसमें मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। बेल्ट एंड रोड फोरम (बीआरएफ) बैठक में 29 देशों और सरकारों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया, जिनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल थे।

रूस, अमरीका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सहित विभिन्न देशों के नेताओं और अधिकारियों ने समारोह में हिस्सा लिया।

भारत ने किया था विरोध

बीती रात कड़े शब्दों में जारी एक बयान में भारत ने कहा था कि संपर्क संबंधी पहल (कनेक्टिविटी इनीशिएटिव) को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि संप्रभुता एवं भूभागीय एकता का सम्मान हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने एक बयान में कहा था इस मामले में हमारी सैद्धांतिक स्थिति के मुताबिक हम चीन से उसकी संपर्क संबंधी पहल वन बेल्ट, वन रोड पर एक सार्थक बातचीत करने का अनुरोध करते हैं जिसका नाम बाद में बदल कर बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव कर दिया गया।

हमें चीन की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

अंडमान निकोबार पहुंचा मानसून, मैदानी इलाकों में बढ़ी गर्मी

नई दिल्ली

मौसम विभाग ने दक्षिणी अंडमान सागर और निकोबार आइलैंड में मानसून के पहुंचने की घोषणा कर दी है। ताजा ऐलान के मुताबिक मानसून की हवाएं अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट से लेकर हट बे तक झमाझम बारिश कर रही हैं। ऐसा पूर्वानुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 24 से 48 घंटों में पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंच जाएगा। इसके बाद मानसून दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के बाकी इलाकों में अपनी बढ़त बना लेगा। गौरतलब है कि अंडमान निकोबार में मानसून ने अपने तय समय से 1 दिन पहले ही दस्तक दे दी है।

मौसम विभाग के डायरेक्टर चरण सिंह के मुताबिक विषवत रेखा से बंगाल की खाड़ी की तरफ मानसून का प्रवाह काफी अच्छा नजर आ रहा है. अपने पहले चरण में यह उम्मीद की जा रही है कि मानसून तेजी से दक्षिणी प्रायद्वीप की तरफ बढ़ेगा। बंगाल की खाड़ी में मानसून की हवाओं के आने के साथ ही दक्षिण भारत में मानसून से

पहले की मौसमी गतिविधियां बढ़ गई हैं। केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में प्री-मानसून बारिश ने तेजी पकड़ ली है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत में प्री मानसून बारिश जोरदार ढंग से कई इलाकों को अपने आगोश में लिए हुए हैं। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 24 से 72 घंटे तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। लिहाजा मौसम विभाग इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उत्तर भारत की बात करें तो यहां पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने जा रहा है और इस वजह से मैदानी इलाकों में तापमान एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं।

एक्सपर्ट्स की चेतावनी

आज फिर हो सकता बड़ा साइबर अटैक, कारोबारियों-संस्थानों के छूट रहे पसीने

नई दिल्ली

रविवार को टेक्निकल स्टाफ इन्फेक्टेड कंप्यूटरों को रीस्टोर करने और बाकियों को सुरक्षा के लिहाज से और चुस्त-दुरुस्त बनाने में युद्धस्तर पर जुट गए। दरअसल, कंपनियों और संस्थानों में डर हावी है कि आज सोमवार को कंप्यूटरों को खोलने पर फिर से रैनसमवेअर का हमला न हो जाए जिसने कार फैक्ट्रियों, अस्पतालों, दुकानों और स्कूलों की गतिविधियों पर अचानक ब्रेक लगा कर दुनियाभर में तहलका मचा दिया।

रैनसमवेअर की चपेट में आई ये देसी कंपनियां

बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन के सिक्यॉरिटी रिसर्चर मैलवेयर टेक ने भविष्यवाणी की कि सोमवार को दूसरा हमला होने की आशंका है। मैलवेयर टेक ने रैनसमवेयर हमले को सीमित करने में मदद की। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक डोमेन का रजिस्ट्रेशन कराए जाने के बाद मैलवेयर टेक का आकस्मिक हीरो के तौर पर स्वागत किया गया। मैलवेयर टेक अपनी पहचान नहीं जाहिर करना चाहता।

उस 22 वर्षीय व्यक्ति ने रविवार को बीबीसी से कहा, हमने इसे रोक दिया है, लेकिन कोई दूसरा आ रहा है और इसे हम नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने कहा, उनके पास इस काम को करने के अच्छे मौके हैं।

इस वीकेंड नहीं, लेकिन इसे सोमवार सुबह तक करने की संभावना है। उन्होंने ट्वीट किया, वानाक्राइ का पहला वर्सन रोक दिया गया, लेकिन दूसरे वर्सन को शायद ही हटाया जा सके। इस हमले से आप तभी सुरक्षित हैं, यदि आप जल्द-से-जल्द मरम्मत कर सकें।

खासकर एशियाई देशों में सोमवार को कंप्यूटर खोले जाएंगे और इस लिहाज से वहां कल का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है जहां शायद अभी सबसे बुरा देखने को नहीं मिला है। सिंगापुर के एक सिक्यॉरिटी रिसर्चर क्रिस्चियन करम ने कहा, इसके बारे में आज (सोमवार) सुबह बहुत कुछ सुनने को मिलेंगे जब यूजर्स दफ्तर आएंगे और शायद फिशिंग ईमेल्स के शिकार बन जाएंगे। हो सकता है उन्हें कुछ और ही परिस्थिति का सामना करना पड़े।

प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स में साइबर सिक्यॉरिटी पार्टनर मैरिन इवेजिक ने कहा कि हमले की बात सामने आने के बाद से ही क्लाइंट्स सिस्टम्स को रीस्टोर करने और सॉफ्टवेयर अपडेट करने में दिन-रात जुटे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने ही पैचेज रिलीज किए थे।

उसने शुक्रवार को भी इसे जारी किया ताकि उस गड़बड़ी को दुरुस्त किया जा सके जिसकी वजह से पूरे नेटवर्क में वॉम फैल जाता है। यह वॉम दुर्लभ और ताकतवर है जिसने शुक्रवार को पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया।

साइबर सिक्यॉरिटी एक्सपर्ट्स की मानें तो 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटरों को लॉक कर देनेवाले वानाक्राइ नाम के रैनसमवेअर के फैलने की गति थोड़ी थमी तो है, लेकिन इससे बहुत कम वक्त तक राहत मिल सकती है। एक्सपर्ट्स की चेतावनी कि रैनसमवेअर के नए वर्सन आ सकते हैं। शुक्रवार के हमले में कितना नुकसान हुआ, इसका अब तक सही-सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका है।जांचकर्ता शुक्रवार को रैनसमवेयर का इस्तेमाल करने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

मेनका गांधी की मांग, दिव्यांग बच्चों के लिए बनाए जाएं विशेष घर

नई दिल्ली

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी चाहती हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष घर बनाए जाएं, क्योंकि चाइल्ड केयर संस्थाएं उनकी निरंतर व स्थायी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को लिखे पत्र में मेनका गांधी ने राज्यों में ऐसे बच्चों के लिए विशेष घर बनाए जाने का अनुरोध किया, जो कि स्थानीय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की निगरानी में गैर सरकारी संस्थानों (एनजीओ) द्वारा संचालित किए जा सकते हैं।

वहीं मेनका गांधी ने सुझाव देते हुए कहा कि जहां छोटे राज्यों को

ऐसे एक या दो सेंटर की तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों को इनसे ज्यादा सेंटर की जरूरत पड़ेगी। जबकि हाल ही में अपने कुछ चिल्ड्रेन होम्स दौरे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि इन संस्थानों में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से एरिया बने हुए थे, मगर वे ऐसी खास सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जिन्हें ऐसे बच्चों की जरूरत है।

ज्यादातर संस्थानों को ट्रांजिशन सेंटर्स के तौर पर संचालित किया जाता है, जहां या तो बच्चों को दोबारा उनके परिवार के साथ मिलाया जाता है या मौजूदा कानून के तहत किसी परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। मेनका गांधी के अनुसार, ऐसे संस्थानों में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके दिल में छेद है या कई अन्य गंभीर बीमारियां हैं और उन्हें विशेष, निरंतर और स्थायी देखभाल की जरूरत है। मगर चाइल्ड केयर संस्थाएं इसमें सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा, मेरा पूरा मानना है कि ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा देखभाल की जरूरत है, ताकि वे एक सम्मानित जिंदगी जी सके।